

देवनारायण योजना में अब तक 445 करोड़ खर्च तीन मंत्रियों ने की योजना की प्रगति की समीक्षा

भदोही/नयागढ़वासी, अठरापुर

देवनारायण बालिका आदर्श छात्रावास अजमेर की विद्युत्कलप स्तरीय से कॉलेज स्तरीय छात्रावास तथा अलावर में कॉलेज स्तरीय बालिका छात्रावास के पवन निर्माण के लिए राजकीय गौरों देवी महिला महाविद्यालय अलावर परिसर में भूमि आर्किटेक्ट के लिए अलग-अलग कंटेनर के प्रस्तावतुसार भिदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग बंधु श्रेष्ठ से एन.ओ.सी. जारी की जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र सिंह राठी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चावुर्वेदी एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेममिंह भडाना ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा कर देवनारायण

योजना की प्रगति की सोमवार को सचिवालय स्थित मंत्रालय भवन में समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि देवनारायण योजना के क्रियान्वयन में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी एवं योजनाओं की समयबद्ध तरीके से प्रगती रंग से पूरा किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि देवनारायण योजनात्मक अब तक 445 करोड़ रु. का व्यय हो चुका है। वर्ष 2014-15 में 121 करोड़ रु. का व्यय हुआ है, जिसमें 60 करोड़ रु. का व्यय विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक योजना पर एवं 7.50 करोड़ रु. का व्यय विशेष पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पर हुआ है।

शर्तों में बदलाव के निर्देश

बैठक में अनुसूचित योजना के निम्न निर्देशों से संबंधित कर पारंपरिक शर्तों में बदलाव निर्दिष्ट करने के निर्देश दिए गए ताकि विभागों में अधिकतम स्कुलों का व्यय हो सके। बैठक में बताया गया है कि अनुसूचित योजना में 4.35 करोड़ रु. का व्यय हुआ है। बैठक में सामाजिक विभाग, अतिरिक्त विभाग के सदस्य अलावर जिला सुपरीन कोष, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक जयदीप कुमार, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक सुभाष चंद्र शर्मा एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

ये होंगे पांच समूह

राठी ने बताया कि पहले समूह में एक मंत्री, दो अधिकारी, एक निजी मंत्री, एक निदेशक, एक मंत्री, एक अधिकारी और दो अधिकारी शामिल होंगे। दूसरे समूह में दो अधिकारी, एक निदेशक, एक मंत्री, एक अधिकारी और दो अधिकारी शामिल होंगे। तीसरे समूह में एक मंत्री, एक अधिकारी, एक निदेशक, एक मंत्री, एक अधिकारी और दो अधिकारी शामिल होंगे। चौथे समूह में एक मंत्री, एक अधिकारी, एक निदेशक, एक मंत्री, एक अधिकारी और दो अधिकारी शामिल होंगे। पांचवें समूह में एक मंत्री, एक अधिकारी, एक निदेशक, एक मंत्री, एक अधिकारी और दो अधिकारी शामिल होंगे।

राठी, चवुर्वेदी
5 अक्टूबर 2015

देवनारायण योजना की समीक्षा

जयपुर (का.सं.)। देवनारायण योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक सोमवार को यहाँ सचिवालय स्थित मंत्रालय भवन में हुई। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजेन्द्र सिंह राठी, सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. अरुण चावुर्वेदी एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेममिंह भडाना ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा कर देवनारायण योजना की प्रगति की समीक्षा की।

गुरुकुल योजना की शर्तों में होगा बदलाव

समीक्षा बैठक

धन की नहीं आणगी कमी

जयपुर, (कास): देवनारायण योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक सोमवार को सचिवालय स्थित मंत्रालय भवन में हुई। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र सिंह राठी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेमसिंह भडाना ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा कर देवनारायण योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि देवनारायण योजना के क्रियान्वयन में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी एवं योजनाओं को समयबद्ध तरीके से प्रभावी ढंग से पूरा किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि देवनारायण योजना-तर्गत अब तक 445 करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है। वर्ष, 2014-15 में 121 करोड़ रुपए का

व्यय हुआ है, जिसमें 60 करोड़ रुपए का व्यय विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर सैद्धिक योजना पर एवं 7.50 करोड़ रुपए का व्यय विशेष पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पर हुआ है। बैठक में गुरुकुल योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन कर भ्रष्टा शर्तों में बदलाव किए जाने के निर्देश दिए गए ताकि जिलों में अधिकांश स्कूलों का चयन हो सके। बैठक में बताया गया कि स्कूटी वितरण योजना में 4.38 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

समीक्षा बैठक में देवनारायण बालिका आदर्श छात्रावास अलवर को विद्यालय स्तरीय से कॉलेज स्तरीय छात्रावास किए जाने की सहमति दी गई। इसके अतिरिक्त अलवर में कॉलेज स्तरीय बालिका छात्रावास के भवन निर्माण के लिए राजकीय गैरी देवी महिला महाविद्यालय अलवर परिसर में भूमि आवंटन के लिए जिला कलेक्टर, अलवर के प्रस्तावानुसार भिदिसक कॉलेज शिक्षा विभाग की ओर से एन.ओ.सी. जारी करने का निर्णय लिया गया।